ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*261. *[The questioner (Shri Prem Chand Gupta) was absent. For answer vide page 23 infra.]*

Prime Minister's Japan Visit

*262. SHRI RUMANDLA RAMACHANDRAIAH: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Prime Minister's visit to Japan has been successful;

(b) if so, whether Japan has agreed to provide aid that was stopped due to the Pokhran test;

(c) to what extent Japanese investment in India would increase; and

(d) if so, to what extent these agreements would help?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI JASWANT SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) Economic sanctions imposed by Japan after India's nuclear tests in May, 1998 were unilaterally lifted by the Government of Japan on 26 October, 2001.

(c) and (d) Prime Ministers of both countries acknowledged that broad and deepened economic relations are an essential underpinning to further strengthen bilateral relations. They shared the view that India's continuing economic reforms, recovery of the Japanese economy through structural reform and the complementarities between the two economies will provide a solid foundation for further enhancing bilateral economic relations.

श्री रूमान्डला रामचन्द्रय्या : सभापति महोदय, पोखरण परीक्षण से पहले जिन चार प्रोजेक्ट्स के लिए हमें जापान से सहायता मिल रही थी वे हैं—मॉडर्नाइजेशन ऑफ कारनूल कडप्पा कैनाल डेवलपमेंट, राजघाट कैनाल मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, मध्य प्रदेश, रांचल इरिगेशन प्रोजेक्ट, उड़ीसा और रिहैबिलिटेशन ऑफ मायनर इरिगेशन टेंक, तमिलनाडु। मान्यवर, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अब यह सहायता मिल रही है या नहीं और अगर मिल रही है तो इनको कब तक पूरा किया जाएगा?

श्री जसवंत सिंह: सभापति जी, जैसा मैं माननीय सदस्य को सूचित कर चुका हूं कि मई, 1998 के अणु परीक्षणों के बाद जापान की तरफ से सहायता रोक दी गई थी, जो अब अक्तूबर में पुनः आरंभ हो गई है। विशेषकर के सिम्हाद्री और दिल्ली का जो अंडरग्राउंड रेलवे का प्रोजेक्ट है उसके लिए यह सहायता है। अन्य जिन योजनाओं का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया कि वह कब तक समाप्त होंगी, यह प्रश्न दूसरे मंत्रालय से संबंधित है।

श्री रूमान्डला रामचन्द्रय्या: सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि भारत और जापान जो आपस में आर्थिक संबंध बढ़ाने के इच्छुक हैं तो क्या जापान ने भारत को यह विश्वास दिलाया है कि चीन का जो प्रभाव एशियन मार्केट पर पड़ रहा है उसको रोकने में जापान कदम उठाएगा? इस संबंध में भारत जापान के साथ क्या कोई विचार कर रहा है?

श्री जसवंत सिंह: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने भारत और जापान के आर्थिक संबंधों के बारे में पूछा तो इन्होंने इसमें चीन की एण्टरी कर दी है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि भारत के किसी भी देश के संबंधों में किसी भी अन्य तीसरे देश की परछाई नहीं है और न ही हम इस रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को चलाते हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी की यात्रा के दौरान चीन को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई। भारत और जापान के जो आपसी संबंध हैं, वह किसी प्रकार से चीन की कोई काट करने के लिए हैं, इस प्रकार का भ्रम माननीय सदस्य अपने में न रखें। हां, आपसी द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को सुधारने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से या माननीय प्रधान मंत्री जी से, जो यहां बैठे हैं, यह जानना चाहूंगी कि क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री जी की यात्रा के दौरान भारत की तरफ से इस तरह का कोई वायदा या इस तरह की कोई अंडरटेकिंग दी गई थी कि भारत सीटीबीटी पर राष्ट्रीय सहमति तैयार करने की कोशिश करेगा? एक ऐसे समय में जब अमरीका एबीएम संधि से अलग हो चुका है, जापान इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रहा, नाराजगी व्यक्त नहीं कर रहा और खासतौर से अमरीका के जो टीएमडी और एनएमडी कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों की भी कोई आलोचना नहीं कर रहा तो इस संबंध में जापान के साथ हमारी क्या बातचीत हुई है? भारत सरकार का इस पर क्या रुख था, क्या राय थी और अब उससे अलग क्या कोई राय ली जा रही है? इन तमाम बातों के बारे में मैं जानना चाहूंगी।

श्री जसवंत सिंह: सभापति जी, जहां तक द्विपक्षीय संबंधों और माननीय प्रधान मंत्री जी की यात्रा से जुड़ा प्रश्न है, तो इस पर प्रधान मंत्री जी का बयान हो चुका है। जहां तक सीटीबीटी का प्रश्न है, भारत की नीति, सरकार की नीति स्पष्ट है, यह कोई जापान जाने से स्पष्ट नहीं हुई बल्कि उससे पहले ही इसके बारे में सरकार ने वर्ष 1998 में अपना पक्ष व्यक्त कर दिया था। इस पर

माननीय सदन में कई बार चर्चा भी हो चुकी है और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इसके बारे में कहा जा चुका है। भारत का अपना एक नीतिगत पक्ष है, जापान का अपना पक्ष है। अभी तक विचारों में अंतर के कारण कुछ दूरी थी, विचारों का अंतर रहते हुए आर्थिक संबंध पुनः सुधरे हैं। जहां तक जापान और भारत के बीच ग्लोबल स्ट्रेटिजिक रिलेशन का है, जब जापान के प्रधानमंत्री मोरे जी यहां आए थे तब इस पर ऐलान हो चुका है। तो इस पर माननीय सदस्या को कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: सभापति जी, मेरा सवाल यह भी था कि जापान का टीएमडी और एनएमडी पर जो रवैया है, उसका एशिया पेसिफिक रीजन पर असर पड़ेगा और इससे अस्त्रों या मिसायलों का जो दौर हमारे क्षेत्र में है, वह तेज हो जाएगी। इस तरह का जो यह खतरा बढ़ रहा है, क्या इसकी ओर आपने जापान का ध्यान आकर्षित किया है?

श्री जसवंत सिंह: सभापति जी, जापान के संयुक्त राज्य अमरीका के साथ अपने द्विपक्षीय संबंध हैं, उनके अपने सामरिक संबंध भी हैं और उन सामरिक संबंधों के रहते हुए जापान का जहां तक मिसायल को लेकर प्रश्न है, चाहे नार्थ कोरिया हो या चीन हो, यह उनका अपना एक सामरिक दृष्टिकोण है। जहां तक स्ट्रेटिजिक इनीसिएटिव या मिसाइल डिफेन्स का सवाल है, इस पर जापान के साथ जो सिक्योरिटि रिलेटेड इस्यूज हैं, उसकी दूसरी बैठक अभी इस साल होने जा रही है। अभी तक यह प्रश्न उठा नहीं है, लेकिन जब बैठक होगी तो उसमें भी इस पर चर्चा की जाएगी।

SHRI KAPIL SIBAL: Mr. Chairman, Sir, with the downturn in the Japanese economy, we are finding that a lot of manufacturing facilities, in fact, Japanese facilities, are shifting to China, because China provides cheap labour; and, because of that a huge amount of investment from Japan, not only through ODA, but also through other forms, is going into China. Now, my question is : During the visit of the Prime Minister, did any discussion take place on increasing the opportunities, because of the low labour cost in India, for setting up industrial units in India, so that we can also take advantage of the huge investments, that are available, which China has already taken advantage of?

SHRI JASWANT SINGH: Yes, Sir; discussions about enhancing, encouraging, and further promoting Japanese investment in commercial areas, outside of the ODA, by Japanese entrepreneurs, took place before the Prime Minister's visit, and are continuing. The

difficulties that the Japanese industry faces in India are being addressed by the Government. I accept, that considering the size of the Japanese economy, considering the size of opportunity that India offers, the investment from Japan—not simply in proportion to a third country, but on its own—is not to the Government's satisfaction. ...*(Interruptions)*...

SHRI KAPIL SIBAL: Did any discussion take place on this particular question?

SHRI JASWANT SINGH: Sir, I am also addressing this question. Yes; Sir, this issue was taken up, but you would appreciate that during a Prime Ministerial visit, the emphasis is given to various issues, and amongst the various issues, the issue related to improving the investment climate and encouraging Japanese investment in India did come up; and that is a continuing exercise.

श्री कुलदीप नैयर: सभापति जी, मेरा यह सवाल स्वयं प्रधान मंत्री जी के लिए है। प्रधान मंत्री जी, आपने वहां पर बड़े गंभीर सवाल लिखे, सोचे, उन पर बहस की, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने 'गीशा' कल्चर की भी स्टडी की? Did you study Geecha Culture?

श्री जसवंत सिंह: सभापति जी, यदि प्रधान मंत्री जी से प्रश्न पूछना है तो इन्हें उसके लिए पहले नोटिस देना होगा। यह प्रश्न विदेश नीति से संबंधित है, माननीय सदस्य अगर कल्चर से संबंधित प्रश्न पूछना चाहते हैं तो इसके लिए वे अगर लिखित रूप से प्रश्न भेजेंगे तो सहूलियत होगी।

श्री बालकवि बैरागी: सभापति जी, वहां जो 'गीशा' है, उसका नाम नीति है, इसलिए आप बताएंगे कि 'गीशा' से आपका कोई सम्पर्क हुआ या नहीं हुआ?

PROF. M. SANKARALINGAM: Sir, in view of the improved relations between Japan and India, after the visit of our hon. Prime Minister, in order to get cheap technology on the production and industrial side, will the Government consider sending a team of experts from the industrial groups to Japan, and get it transferred to India?

SHRI JASWANT SINGH: Sir, there is already an 'eminent persons group' between India and Japan. In fact, this group comprises really eminent persons from diverse fields on national

activity. They address themselves to this aspect. Now, so far as the question regarding transfer of technology is concerned, both Japan and India are currently focussing on and concentrating on mutual exchange of expertise on information technology. Now, there are great complementarities between the two countries, in terms of expertise. My friend and colleague, the Minister of Communications and Information Technology, has also visited Japan. The cooperation in this field is significantly advanced. And we believe that this is one field in which the complementarity of the strengths of the two economies of the countries is such that they can very effectively be shared. This is in progress.

प्रो॰ राम गोपाल यादव: सभापति महोदय, पिछले कुछ वर्षों से हमारी सरकार दुनिया के दूसरे देशों के साथ शीर्ष स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भारत को एक स्थाई मेंबर के रूप में सम्मिलित किए जाने के लिए प्रयास कर रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या जापान की यात्रा के दौरान इस संबंध में जापानी नेतृत्व से कोई चर्चा हुई और अगर हुई तो क्या जापानी नेतृत्व ने भारत के इस दावे पर अपनी सहमति जताई कि भारत सुरक्षा परिषद का स्थाई मेंबर हो?

श्री जसवंत सिंह: सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह सूचित करना चाहूंगा कि जहां तक संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता का प्रश्न है, माननीय प्रधानमंत्री जी की यात्रा से पहले भी द्विपक्षीय बातचीत में जापान के साथ इस संबंध में चर्चा हो चुकी है। जब मैं वहां गया था, तब बातचीत हुई थी और उसके उपरांत जब उनके प्रधानमंत्री जी यहां आए, तब बातचीत हुई। जापान ने अपना स्पष्ट मत व्यक्त किया है कि भारत और जापान, दोनों को संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधारों के लिए, विशेषकर सुरक्षा समिति के स्थाई सदस्यों के लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए क्योंकि भारत और जापान के हितों में किसी प्रकार का अंतर्द्वंद्व नहीं है। हम भी चाहते हैं कि जापान और भारत इस दिशा में साथ मिलकर काम करें और जो संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया था, उसमें यही विचार व्यक्त किए गए थे।

श्री नरेन्द्र मोहन: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विदेश मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्रा के दौरान क्या भारत जिस आतंकवाद से जूझ रहा है, उस पर कोई चर्चा हुई? महोदय, भारत लंबे अरसे से एक छद्म युद्ध से जूझ रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस बारे में क्या कोई विशेष चर्चा हुई या कोई विशेष आश्वासन मिला? हमारा पड़ोसी देश जिस तरह हमें परेशान कर रहा है, उसको लेकर क्या कुछ बातें हुई?

श्री जसवंत सिंह: सभापति महोदय, जहां तक आतंकवाद का प्रश्न है, माननीय प्रधानमंत्री जी

की यात्रा के दौरान और उससे पहले भी जापान ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के विचारों से सहमति प्रकट की थी और हमारा जापान के साथ सहयोग भी चल रहा है, विशेषकर sea lanes piracy को लेकर, जहां हमारी नौसेना और हमारे कोस्ट गार्ड्ज़ ने जापान के साथ सहयोग किया है। इसके उपरांत जापान ने खुला वक्तव्य दिया है और घोषणा की है कि जो भारत का कांप्रिहैंसिव कन्वैंशन ऑफ टैररिज्म है, जिसका एक प्रारूप संयुक्त राष्ट्र संघ में पड़ा है, जापान चाहता है कि वह जल्दी से जल्दी ऐडॉप्ट हो और वह इसमें भारत को पूरा सहयोग देगा। इसे अतिरिक्त माननीय सदस्य जानते हैं कि 11 सितंबर की घटना के बाद जापान अंतर्राष्ट्रीय कोऐलेशन का हिस्सा हो गया है और जापानी नौसेना बेड़े, कोऐलेशन के बेड़ों के साथ काम कर रहे हैं। अतः जापान इस परकार के आतंकवाद के खिलाफ है।

Amendment to Industrial Disputes Act, 1947

*263. SHRI KARNENDU BHATTACHARJEE: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-report captioned "Central labours to make lay-offs easy" which appeared in the 'Newstime dated the 23rd February, 2002; and

(b) the safeguards taken/proposed to be taken to protect interests of labour before amending the Industrial Disputes Act, 1947 to lay off employees without Government's permission?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI SHARAD YADAV): (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Attention of the Government has been drawn to the news-item which appeared in the Newstime dated 23rd February, 2002.

(b) Amendments to various labour laws are brought about keeping in view the requirements of the social partners and after ensuring that the workers interests are fully protected. The Hon'ble Finance Minister in his Budget Speech in February, 2001 had indicated the Government's intention to amend the Industrial Disputes Act, 1947. It had been proposed in the said Budget Speech that the provisions of Chapter VB of the I.D. Act may now apply to the industrial establishments employing not less than